REPLY TO THE DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF LABOUR

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति जी, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि जो श्रम मंत्रालय है उसे और उसके काम पर बहस के लिए सबसे पहले इस सदन में, इस सत्र में चर्चा के लिए आपने इसे स्वीकृत किया। माननीय सदस्यों ने उत्साह से अपनी पूरी, सम्पूर्ण चेतना और अपने अनुभव से विस्तारपूर्वक सवाल उठाने का काम किया। मैं मानता हूं कि जो सवाल उन्होंने उठाए उनमें से बहुत से सवाल मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं है कि उन्होंने जो बातें उठायी हैं वे बातें हमारे लोकतंत्र और लोकशाही के लिए ...**(व्यवधान)**... जो हमारे 52 वर्ष आजादी के हैं उसमें हिंदुस्तान का जो अंतिम आदमी है, जो लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं, उन लोगों की जिस हालत का चित्रण सदस्यों ने किया, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूं।

इस बहस को जीवन राय जी ने शुरू किया था। श्री रामचन्द्र खूंटिआ, श्री संघ प्रिय गौतम, श्री रामचन्द्रैया, श्री पेरूमल, श्री विरुम्भी, श्री मूल चन्द, श्री प्रेमचन्द गुप्ता, श्री जे. चितरंजन, श्री एकनाथ केशव ठाकुर, श्री लाजपत राय, श्रीमती बिम्बा रायकर, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री गांधी आज़ाद, श्रीमती जमना देवी जी - इतने सदस्यों ने इसमें कल हिस्सा लिया। कुछ माननीय सदस्यों के समय में मैं नहीं रह सका था।

मुख्य तौर पर जीवन राय जी ने जो बातें कहीं उसमें उनकी चिंता है कि खास करके जो ग्लोबलाइजेशन है, जो नयी रिजीम आई हुई है, उस रिजीम के चलते रोज़गार घटे हैं। आर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगे हुए काफी लोग बाहर निकले हैं और मैं मानता हूं कि 1.3 परसेंट लोग जो रोजगार के लिए आए हैं उनकी कमी हुई है, .99 परसेंट हो गए हैं। यह आपकी जो बात है, सच है। लेबर रिफार्म्स जो हैं, उनमें जो आर्गेनाइज्ड लेबर हैं, मजदूर हैं उनकी चिंता आपको थी। खूंटिआ जी ने भी बहुत विस्तार से चीजों को रखा और उनका एक मामले में, जो कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना है उसके बाबत हमारे और उनके बीच में मतभेद हैं, मैं उस पर उनसे बात करूंगा । उस योजना में खास करके अन-ऑर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में, एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में, जो आपकी चिंता है, वह चिंता की शुरुआत है, एक छोटा सा कदम है और वह कदम कारगर है। इसके बावजूद आपकी जो चिंताएं थीं, आपने बहुत विस्तार से कहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है या जो इस देश के मज़दूर हैं, जो मेहनतकश हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनको ही दोष दिया जा रहा है । लेकिन सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है । ये जो यहां पहुंचे हुए लोग हैं, उसमें सब से ज्यादा राजनीतिक लोग, फिर ब्यूरोक्रेसी यानी पूरा सिस्टम पहले जिम्मेदार है और इस देश में जो श्रम करने वाले हैं और जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, वे तो मेहनत करते ही हैं । यह बात कहीं नहीं है कि उनको ही टॉर्गेट किया जा रहा है या उनके ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जा रही है कि हिन्दुस्तान में जो भी रिफॉर्म हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके चलते रुकी रही हैं या उनके चलते बिगड़ रही हैं । मैं खूंटिआ जी से कहना चाहता हूं कि सरकार उतनी ही चिंतित है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चिंता आपकी है वही चिंता हमारी भी है और इस चिंता के प्रति जितने आप बेचैन हैं, भले ही उससे थोड़े बहुत कम हों, लेकिन हमारी बेचैनी भी आपसे कम नहीं है । ...**(व्यवधान)**... संघ प्रिय गौतम जी ने जो बात

सब से ज्यादा मार्मिक ढंग से रखी, उन्होंने हिन्दुस्तान की जो अन-ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो गिट्टी-मिट्टी तोड़ती है, रिक्शा-टांगा चलाती है, उन्होंने कहा कि मैं तो एग्रीकल्चर लेबर के घर से ही आया हूं, निश्चित तौर पर हिन्दुस्तान में 52-54 वर्षों में जो सब से बड़ा संकट है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाए हैं, हिन्दुस्तान की पूरी वर्क फोर्स के 93 परसेंट लोग अन-ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी असंगठित मजदूर हैं । जो डेली वेजेज़ हैं और जो बाकी मजदूर हैं, जो संगठित हैं, वे 7 परसेंट हैं और उन्हें ही सामाजिक सुरक्षा थोड़ी-बहुत मिली हुई है । उसमें भी खामियां हैं। चाहे ई.पी.एफ. की स्कीम है, चाहे ई.एस.आई की स्कीम है, मैं नहीं कहता कि वे परफैक्ट हैं । मैं जब से आया हूं तब से लगा हूं कि उनमें कैसे सुधार हो । उनमें जो खराबियां हैं, जो खामियां हैं, कैसे उनको दुरुस्त करने का काम हो सके । लेकिन सभापति जी, एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि जो ई.पी.एफ है इतना बड़ा कॉर्पस है, हिन्दुस्तान में इतनी तरह के घपले और बातें कही जाती हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की यह पचास वर्ष पुरानी जो संस्था है, इसमें आज तक एक भी घोटाला या घपला सामने नहीं आया । जो माननीय सदस्यों ने एक-दो बातें कही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्रेमचन्द गुप्ता जी नहीं हैं, ई.पी.एफ. में या किसी कर्मचारी के साथ यदि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो, तो कोई भी माननीय सांसद् अगर मुझे खबर करेगा तो निश्चित तौर पर, सभापति जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि उसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतूंगा और सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा और जो मेरे हाथ में सामर्थ्य होगा उसके अनुसार उसको ठीक करने का काम होगा । लेकिन पचास साल में यह तो मानना पड़ेगा कि इस संस्था को देख करके हम कह सकते हैं कि इस देश में ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटेबिलिटी की जो बात है, ये दोनों चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं । जो ई.पी.एफ. है, जो प्राविडेंट फंड है, उसका जो सब से बड़ा ट्रस्ट है वह सी.बी.टी. अर्थात् सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ है, उसमें हिन्दुस्तान भर के रिकोग्नाइज्ड यूनियंस के लीडर हैं यानी रिकोग्नाइज्ड यूनियंस उसमें लोगों को पहुंचाती हैं । उसमें एम्प्लायर होते हैं, सरकार के लोग हैं, हम पालिटीशियन लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं । उनके चलते इतनी बड़ी संस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ करने की कोई गुंजायश ही नहीं है । इसमें सारे लीडर्ज़ जिनको शरीक किया गया है, मैं आपके माध्यम से सदन में कंफैस करना चाहता हूं कि वे संगठित मज़दूर लोगों के लिए जरूर काम करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यदि यह राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के हाथ मे हो तो बहुत सी संस्थाओं में जिस तरह का घपला हुआ है, वैसा ही इसमें भी कोई न कोई घपला जरूर होता, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं वे उसमें शरीक हैं। मेरा अनुभव यह कहता है कि उनके चलते यह जो इतना बड़ा कॉर्पस है इस देश में रिज़र्व बैंक के बाद यह सब से बड़े कॉर्पस में आता है। इसमें कोई अमानत में ख़यानत नहीं है । आप ने ई0एस0आई0 का सवाल उठाया । मैं मानता हूं कि ई0एस0आई0 को स्वास्थ्य की सुरक्षा का जो काम दिया गया है, वह निश्चित तौर पर एक बड़ा काम है । हिंदुस्तान में केन्द्र सरकार के पास अगर हैल्थ का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वह ई0एस0आई0 हॉस्पीटल्स का है । आप जानते हैं कि उस में केन्द्र सरकार 8 परसेंट देती है ...**(व्यवधान)**... लेकिन उस के बावजूद उस में दिक्कत यह है कि उन सारे हॉस्पीटल्स को स्टेट गवर्नमेंट्स रन करती हैं । मैं मानता हूं कि बहुत सी सूबाई सरकारें उन को अच्छी तरह से चला रही हैं हालांकि खूंटिआ जी कहेंगे कि कोई सरकार अच्छी तरह नहीं चला रही है ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचन्द्र खूंटिआ (उड़ीसा): ई0एस0आई0 8 परसेंट देती है, केन्द्र सरकार कुछ नहीं देती है ।

श्री शरद यादव : आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसे सुधार लेता हूं । लेकिन आप जानते हैं ई0एस0आई0 के सभी हॉस्पीटल्स सूबाई सरकारें चलाती हैं । उन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा हम देते हैं, ई0एस0आई0 बोर्ड देता है । वह हमारे मंत्रालय से जाता है । निश्चित तौर पर उस में जिस तरह की कल्पना थी, उस के अनुसार काम नहीं हो रहा है । अब हमारी कोशिश है कि देशभर के जितने सूबे हैं, उन में मॉडल हॉस्पीटल्स बनाएं । उस के लिए 5-7 सूबों से प्रस्ताव आ गया है और मेरा मानना है कि महीने, दो महीने में सभी सूबों से यह आ जाएगा । आज सूबाई सरकारें आर्थिक तौर पर बहुत विपन्नता की स्थिति में हैं, हम उस दिक्कत को जानते हैं । इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक स्टेट में एक मॉडल हास्पीटल बनाएं। "एम्स" के बराबर तो नहीं, लेकिन उस के जैसे दो सेंटर्स बनें जिन में सब्सक्राइबर्स को सब तरह का अच्छा और महंगा इलाज मिल सके । ऐसे दो हॉस्पीटल्स बनाने का काम होने वाला है और उस के लिए मनी भी एलोकेट कर दिया है । जो बॉर्डर हॉस्पीटल्स हैं, उन के लिए भी मनी एलोकेट कर दिया है और सूबाई सरकार अगर अपनी इच्छा से हॉस्पीटल देना चाहती है तो हम निश्चित तौर पर उस के लिए भी तैयार हैं । जो हॉस्पीटल हमें सौंपा जाएगा, उसे चलाने के लिए ई0एस0आई0 सीधे तैयार है । जीवन रॉय जी की चिंता कानून के बदलाव और खासकर आई0डी0 एक्ट व कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के बारे में ज्यादा थी । मैं उस पर बाद में आऊंगा ।

सभापति जी, माननीय संघ प्रिय गौतम जी ने असंगठित मजदूरों की बात की । महोदय, आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो नई परिस्थिति पैदा हुई है, उस से दुनिया बहुत करीब-करीब आ गयी है और यह चुनौती हमारे सामने ही नहीं, दुनिया के हर देश के सामने है । अब उस चुनौती का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाकर उस चुनौती का मुकाबला करें बल्कि चिंता यह है कि उस चुनौती का हम कैसे मुकाबला करें । आज चाहे हिंदुस्तान में मजदूर लोग हों या और लोग हों उन में सब से बड़ी चिंता का कारण आज जो मैं समझ सका हूं वह वर्तमान परिस्थिति में बदलाव या परिवर्तन की है । मान लो अगर किसी कारखाने में डिस-इनवेस्टमेंट हो गया तो आज हिंदुस्तान में सामाजिक सुरक्षा इतनी कम और कमजोर है कि ये मजदूर सीधे रोड पर चले जाएंगे और उन को कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं होगा । इसलिए आज सारी दुनिया में सब से बड़ी बहस जो चल रही है और इस सदन में पहले भी बहस हुई है कि इस देश में सामाजिक सुरक्षा का कोई ढांचा या कोई अम्ब्रेला नहीं है । जो हिंदुस्तान का मजदूर है, श्रमिक है - चाहे वह डेली वेजेज का हो या कांट्रेक्ट लेबर हो या आर्गनाइज्ड लेबर हो, उन सभी की एक चिंता है कि इस देश में सामाजिक सुरक्षा का कोई अम्ब्रेला नहीं है । सभापति जी, जब से हमारी सरकार आई है, तब से पांच सामाजिक सुरक्षा के काम हमारे हाथ में हैं, लेकिन मैं एक बात पर कनफेस करता हूं और मानता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, मैंने देखा है कि जो सुरक्षा हम ने दी है, जैसे कि बीड़ी मजदूरों के लिए दी है, वह जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि उस का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए । उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए । हमारे वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, हिन्दुस्तान की जो कृषि लेबर है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी उम्र-दराज होने पर उसकी जिंदगी में जो दिक्कत होती है उसको देखते हुए पिछले साल इन्होंने एक कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी । इस योजना में एक लाख लोग आ गए हैं । यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वह कारगर कदम है, जिसके चलते हिन्दुस्तान के खेतिहर मजदूर की सुरक्षा का एक बड़ा संस्थागत विस्तार करने का हम काम करेंगे । अगर हम यह काम पूरा नहीं करते तो

हिन्दुस्तान में किसी तरह का परिवर्तन चलेगा नहीं । इस तरह हमारे पास पांच-छह सामाजिक सुरक्षा योजना हैं, जिनका विस्तार करने का हमारा काम है ।

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर पिछले दो-तीन साल में एम्पलायमेंट घटी है, लेकिन सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं भारत सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से घोषित हुई हैं, उन योजनाओं से तकरीबन तीन करोड़ से ज्यादा रोजगार के सृजन का रास्ता खुलेगा । जो अनआर्गेनाइज्ड लेबर है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, बीड़ी वर्कर है, सिने वर्कर है,जिनके मालिक को पहले एकड़ा जा सकता है, जिनको किसी तरह से इकट्ठा करने का काम हो सकता है, वह करने का काम किया जाएगा । कल तमिलनाडु के हमारे साथी विरुम्मी जी बोल रहे थे, मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, कर्नाटक में, हिन्दुस्तान में सामाजिक सुरक्षा के लिए यह सरकार पूरा प्रयास कर रही है । विरुम्मी जी आज यहां उपस्थित नहीं हैं, मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में प्रयास चल रहे हैं, चाहे रिक्शे वाले हैं, चाहे तांगे वाले हैं, चाहे ताड़ी वाले हैं, उन सब के लिए अलग-अलग बोर्ड और संस्था बनाए जा रहे हैं । उन बोर्ड और संस्थाओं का काम समझने के लिए भारत सरकार, हमारा मंत्रालय अध्ययन कर रहा है ।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमने सेकेण्ड लेबर कमीशन बनाया है, जिसमें श्री रवीन्द्र वर्मा, जो खुद श्रम मंत्रालय में रहे हैं, वह इसके चेयरमैन हैं । इसकी रपट दो महीने में आने वाली है । उनको यह सारी चीजें सौंपी गई हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद उसे सदन में हम लाएंगे । जो चिंताएं यहां माननीय सदस्यों ने रखी हैं, जो भाषण माननीय सदस्यों ने यहां किए हैं, जो इतने बढ़िया और बेहतर हैं, आंकड़ों से सज्जित हैं, उनको भी हम इस कमीशन को अध्ययन के लिए देंगे । हम मानते हैं इन भाषणों में जमीन की हकीकत भी है क्योंकि यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, वह जमीन से जुड़े लोग हैं । मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि अगर इन बातों को जमीन पर उतारने का काम हो जाए तो हमारा देश तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है । मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों ने जो यहां बोला है, उसको हम कमीशन को देने का काम करेंगे ।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में एक असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी का एटमोसफियर फैलाया जा रहा है कि हमारी सरकार जो है वह कानून में तब्दीली करना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से कानून ऐसे हैं, जैसे माइन्स एक्ट है, दूसरे एक्ट हैं, पुराना वेजेज एक्ट है, जहां बदलने की जरूरत है, वहां वैसा काम करना होगा । कुछ एक्ट हमने बदले भी हैं, जैसे एमीग्रेशन एक्ट है, उसको बदला है और कुछ कानून तो इतने पुराने हैं, जो सिर्फ किताबों में पड़े हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : सर, जवाब तो आ नहीं रहा ।...**(व्यवधान)**... कम से कम बोनस वाला जो है उसकी अपर सीलिंग, लोअर सीलिंग बढ़ा दीजिए । ऐसा कुछ एनाउन्स कर दीजिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : सभापति जी, इतना बड़ा सवाल माननीय सदस्य हमारे सिर पर डाल रहे हैं ।

श्री जीवन राय : सर, यह एक छोटी सी चीज है । नौ साल बाद हाउस में लेबर पर डिसकसन हो रहा है । आप उनके लिए छोटी सी राहत दे दीजिए ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, जीवन राय जी बहुत ही हिकमत वाले आदमी हैं । हम पर इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं कि फाइनेन्स मिनिस्टर, जो पास में बैठे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा गड़बड़ मत कर देना । ...**(व्यवधान)**...

श्री जीवन राय : कम से कम उधर से आप एनाउन्स तो कर दीजिए ।...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : आपकी जो भावना है, आपकी जो बात है, उसके लिए तो मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि भारत की किस तरह की वित्तीय हालत है । ...**(व्यवधान)**...

श्री जीवन राय : सर, पूर्व मंत्री जटिया जी के टाइम में सब तैयार हो गया था । आर्डर साइन होने थे, लेकिन हुए नहीं ।...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : जीवन राय जी, एक बात समझ लीजिए कि पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूरे सूबे बर्बाद हो गए । आप जानते हैं कि देश की जो वित्तीय हालत है, तो जितनी हमारी चादर होगी उतने ही पैर फैलाएंगे न । आपने जो सुझाव रखा है, सरकार उस पर विचार कर रही है लेकिन विचार का मतलब यह नहीं है कि आपकी बात को ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचन्द्र खूंटिआ : क्या यह सच है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ सभी नेशनल ट्रेड यूनियन्स की डिस्कशन के समय गवर्नमेंट की तरफ से यह ऐश्योरेंस दिया गया था कि बोनस एक्ट को तुरंत अमेंड किया जाएगा, क्या यह सच है या नहीं और अगर सच है तो अभी तक इस पर डिसीजन क्यों नहीं हुआ है ?

श्री शरद यादव : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि श्री जीवन राय जी और बाकी सदस्यों ने, संघ प्रिय गौतम से लेकर खूंटिआ जी तक, सबसे ज्यादा सोशियल सिक्युरिटी के मामले में अपनी चिंता व्यक्त की है, हरेक मैम्बर ने अपनी तरह से यह चिंता व्यक्त की है । आरगेनाइज्ड लेबर के बारे में अच्छा काम हुआ है, मैं यह मानता हूं कि जो भी ट्रेड यूनियन के लोग हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि जो आरगेनाइज्ड है, उसे प्रोटेक्शन मिल जाए और उनको तो थोड़ा-बहुत प्रोटेक्शन मिला हुआ है । ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचन्द्र खूंटिआ : सर, मेरा सवाल स्पेसिफिक है ।

Sir, my question is very specific. While discussing the matter with all the trade unions, the Prime Minister assured them that the Bonus Act would be amended. I want to know whether a decision has been taken or not. If a decision has been taken, and if the Prime Minister has assured, why is the Government hesitating to announce it?

श्री शरद यादव : सभापति जी, मुझे यह तो मालूम है कि मुलाकात हुई थी, मगर उसमें क्या समझौते हुए, क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं पता लगा लूंगा ।...**(व्यवधान)**... जीवन राय जी, आप तो दुर्गापुर में भी थे ।...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : आप सब जगह रहते हो ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, चाइल्ड लेबर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान में स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर ऐजुकेशन केवल 5 परसैंट है, उसे कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में कई सुझाव आए हैं और इक्वल वेजिस के बारे में सुझाव आए हैं, ये गंभीर सवाल हैं, इन सब पर सदन में जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं निश्चित तौर पर उससे सहमति व्यक्त करता हूं कि इस बारे में जो काम होना चाहिए था, उससे हम बहुत दूर हैं । इसे ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए जितने वेलफेयर बोर्ड हैं, आपके ई0एस0आई0 के जितने बोर्ड हैं और इस बारे में सब मंत्रालयों में जितनी तरह के काम हो रहे हैं, मैंने जब से मंत्रालय का जिम्मा लिया है, तब से मैंने कितनी मीटिंग इस बारे में की हैं, मैं उसकी गिनती आपको नहीं बता सकता। आपने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उस काम में लगा हूं ।

अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिस पर हमारे मंत्रालय की इस बहस में सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की गई है और बाहर भी जिस बारे में सबसे ज्यादा चिंता है, वह है आई0डी0एक्ट और कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के बारे में । इस पर विवाद है और विवाद पर बहस जारी है । हमारे ग्रुप आफ मिनिस्टर में भी ईश्यू है, कांट्रेक्ट लेबर ज़ेरे बहस है । मैं सदन को इतना ही कह सकता हूं कि देश के हित को देखते हुए जो इंडस्ट्री है, जो रोज़गार और बेरोज़गारी है, जो आरगेनाइज्ड लेबर है, इन सबके हितों को देखकर इसमें आगे बढ़ा जाएगा और इतना आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री जीवन राय : बगैर यूनियन से बात किए । बिना कुछ किए यूनियन को खुश कर रहे हैं ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, यूनियन के साथ हम सब मंत्री हैं, रात-दिन हम बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि उनकी क्या भावना है, सरकार जानती है उनकी क्या भावना है । आप जो यूनियन से बगैर बात करने वाली बात कह रहे हैं, तो सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सारे अपोजीशन, अपोजीशन से लेकर हमारे सब लोगों की ट्रेड यूनियन है, बातचीत किए बगैर, सबसे बातचीत किए बगैर लेबर रिफार्म्स के बारे में ऐसे सीधा नहीं आया जाएगा, हम सोचेंगे और आपके पास आएंगे । यह भी जान लीजिए कि हम यहां खुले मन से आएंगे, खुले दिल से आएंगे, खुले दिमाग से आएंगे ।

श्री सभापति : एक बज गया है, अब समाप्त कीजिए ।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो आर्गनाइज्ड लेबर है, निश्चित तौर पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है । उनके संबंध में जो भी

अमेंडमेंट लाए जाएंगे, जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, वे सबसे चर्चा करके ही यहां लाए जाएंगे । धन्यवाद ।

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair

THE APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2002

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2002-03, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the amounts provided in the Bill are inclusive of the sums already authorised in the Appropriation Vote on Account Act, 2002 (No. 22) of 2002.

The question was proposed.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttaranchal): Sir, is there any speaker? Everybody on that side is interested in listening to the speeches of their leaders in the Lok Sabha. It would be better if we pass it without discussion.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमाशंकर कौशिक) : आप तो बोलने वालों में हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : हमारी तरफ से कोई नहीं बोलने वाला। लोक सभा में आज सोनिया जी का भाषण चल रहा है। सब लोग वहीं हैं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता(बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, एप्रोपिएशन बिल पर तो डिसकसन